WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जवाहर रोजगार योजना का मूल्यांकन

*266. **श्री कैलाश नारायण सारंग :**
श्री वीरेन्द्र जे० शाह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने जवाहर रोजगार योजना का मूल्यांकन करके अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना के अधीन 1989–90 और 1990–91 के वर्षों में प्रति व्यक्ति क्रमशः औसतन 11.44 और 15.68 दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के और गैर पारम्परिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी०ई०ओ०) द्वारा जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) का एक द्रुतगामी अध्ययन शुरू किया गया था और अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है ।

(ख) अध्ययन रिपोर्ट, के अनुसार, चुनिंदा ग्राम पंचायतों ने, जिन्होंने निधियों का उपयोग किया था, 1989–90 और 1990–91 के दौरान प्रति व्यक्ति क्रमशः औसतन 11.44 तथा 15.68 दिन के लिए रोजगार प्रदान किया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up of Food processing units for utilising grapes

*267. SHRI SOM PAL:
DR. NAUNIHAL SINGH:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state

(a) whether it is a fact that in the absnece of adequate food processing arrangements, grapes and citrus fruits cultivators are facing acute problem of marketing their produce;

(b) whether it is also a fact that there is a demand for putting up food processing units to utilise surplus produce of these items in India;

(c) whether it is also a fact that valuable foreign exchange can be earned by exporting these processed items; and

(d) if so, what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Farmers face problems of marketing grapes and citrus fruits in the period of glut ue to; *inter-alia,* an adequate processing facilities and post-harvest infrastructure.

(b) and (c) Yes, Sir.

(d) Government is implementing various schemes to achieve these objectives like (i) Market Intervention Scheme; (ii) Schemes for assisting State Governments, Public Sector Undertakings etc. for establishment|diversification|modernisation of fruits and vegetable processing units including post harvest processing units; (iii) National Cooperative Development Corporation's Assistance Scheme for development of post harvest infrastructure and